5. While no particular date is fixed for the commencement of the service, depending upon the end of the monsoon, it is operated usually from early September to about middle of May in the following year. The services remain suspended during the monsoon period The present operators were not agreeable to incur any expenses on annual survey inspection of the vessels this year unless a decision on their request for an increase in passenger fares was taken by the Government in advance. Since in any case the ships have to undergo special survey before the services can commence, the operators were asked to get the vessels surveyed on the assurance that if the service was taken over by the Government, the expenses incurred by the Company on the survey of vessels would be reimbursed while fixing the compensation amount. Accordingly, the company is getting the vessels surveyed and they are expected to be ready for service by about the third or last week of September.

6. It would, therefore, be appreciated that the Government has been confronted with a situation in which (a) the present operators demanded fare increase which was opposed by the people and the Government of Maharashtra, who have also expressed their dissatisfaction with the present services; (b) the Government of Maharashtra who were requested to take over the services themselves has not shown any willingness to do so; (c) the public sector shipping companies who were also asked to consider taking over the service have shown their reluctance to do so without the assurance that they would be allowed to charge economic fares. It may further be pointed out that the present operators have not only asked for an increase in the fares but have also demanded a structure of passenger fares that ensures them a 10 per cent return on their equity capital. In this situation all possible efforts are being made to find out a basis for the earliest resumption of the Konkan services satisfactory to the users, after the end of the monsoon. The matter is being attended to with all due expedition and urgency in consultation with the Government of Maharashtra.

MR. SPEAKER: We now adjourn for lunch. Mr. Narsingh Narain Pandey will speak on the Bill after lunch.

**13.02 hrs.**

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.*

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen Hours of the Clock*

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

## COKING AND NON-COKING COAL MINES (NATIONALISATION) AMENDMENT BILL—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER. We shall take up clause-by-clause consideration of the Coal Mines Nationalisation (Amendment) Bill, Shri N. N. Pandey

**श्री नरसिंह नारायण पांडे** (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज 4 का, जो सदन के सम्मुख विचार के लिये प्रस्तुत है, समर्थन करता हूं और इस क्लाज के संबंध में जो संशोधन पेश किये गये है, उन का विरोध करता हूं ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान गोरखपुर लेबर आर्गनाइजेशन की ओर दिलाना चाहता हू । गोरखपुर लेबर आर्गनाइजेशन 1942 से देश के विभिन्न कोलफील्डज में, और सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों में, जहां जरूरत पड़ती थी, मजदूर भेजा करता था और इसके लिए उसके द्वारा लेबर का रिक्रुटमेंट होता था । वहा रिकार्ड आफिस, लेबर हास्पिटल और वैलफेयर स्कीम भी चल रहे थे और यह डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के मातहत काम करता था ।

कोल नेशनलाइजेशन के बाद सी० आर० ओ० को एबालिश कर दिया गया और वह हम सब लोगों के समर्थन से एबालिश किया गया । मजदूरों की बहुत बड़ी रकम, जो छब्बीस लाख रुपये के लगभग है, अभी तक सी० आर० ओ० के ऊपर बाकी है, जिसका

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

अभी पेमेंट नहीं किया गया है । वेलफेयर स्कीम का पैसा और मजदूरों के फंड का पैसा अभी तक सी० आर० ओ० के जिम्मे बाकी है । प्रश्न यह है कि उस पैसे का क्या होगा । यह पैसा पूर्वी क्षेत्र के ग्यारह जिलों के गरीब मजदूरों का है, जो विभिन्न कोयला खदानों में काम करते थे । आखिर उस पैसे का एडजस्टमेंट कैसे होगा ?

उस पैसे के एडेजस्टमेंट के बारे में इस क्लाज में कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है । वह बहुत ही सुखदायी प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि उस से उन मजदूरों को लाभ होगा, उन की स्थिति में सुधार होगा ।

लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व मंत्री, श्री मोहन कुमारमंगलम ने इस बारे में कुछ एशोरेंसिज दिये थे और कपालियामेंटरी कमेटी बनाने की बात कही थी, जो इस बात पर विचार करे कि गोरखपुर सी० आर० ओ० के एक्वायरिंग के बाद गोरखपुर लेबर आर्गनाइजेशन का क्या होगा और कैसे गोरखपुरी मजदूरों को बार्डर रोड आर्गनाइजेशन आदि में खपाया जाये । उत्तर प्रदेश की सब से बड़ी समस्या यह है कि हमारी धरती पर आज बहुत अधिक बोझ है और चालीस फीसदी मजदूर बाहर जा कर काम करते हैं ।

आज मुझे मालूम हुआ है कि गोरखपुर लेबर आर्गनाइजेशन को चालू करने के लिए जो एशोरेंस दिया गया था, उसको एक आफिशल कमेटी बनाकर समाप्त किया जा रहा है । 14 मार्च को जो कमेटी बैठी थी, जिसमें लेबर मिनिस्टर, भूतपूर्व मंत्री, श्री कुमारमंगलम, और विभाग के अधिकारी थे, उसमें पार्लियामेंट के मेम्बरों को जो सालम एशोरेंसिज दिये गये थे, उनके बारे में क्या होगा ?

हमारे लिए यह जन्म-मृत्यु का प्रश्न उपस्थित हो गया है ? गोरखपुर के उस लेबर आर्गनाइजेशन का आज क्या हश्र होगा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों को देश के कोने कोने में, जहां जरूरत पड़ती थी, भेजता था ? मैं चाहूंगा कि भूतपूर्व मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये थे, मंत्री महोदय उनको पूरा करें और सदन को इसके बारे में कैटागारिकल एशोरेंस दें । जब तक सरकार कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करती है, जब तक वह गोरखपुर लेबर आर्गनाइजेशन को सेंट्रल लेबर आर्गनाइजेशन का रूप नहीं देती है, या कोई ऐसा रूप नहीं देती है, जिसके अन्तर्गत उन मजदूरों की व्यवस्था किसी दूसरे ढंग से हो सके, तब तक रिकार्ड आफिस को न तोड़ा जाये, वेलफेयर स्कीम के फंड को न घटाया जाये और बीस बैडज के हास्पिटल को न खत्म किया जाये ।

क्लाज 4 की जो मंशा है, उसका स्वागत करते हुए मैं मंत्री महोदय से यह एशोरैंस चाहता हूं कि जो आश्वासन इस सदन में भूतपूर्व मंत्री, श्री मोहन कुमारमंगलम, और लेबर मिनिस्टर ने दिया था उसको पूरा किया जाएगा । अगर जरूरत पड़े तो इस संबंध में कोई पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाये जो जा कर सारी सिचुएशन को देखे और इस बारे में जांच करे । यह सब जिम्मेदारी अफसरों पर नहीं छोड़ देनी चाहिये ।

इस बारे में कई कमेटियां बन चुकी हैं । विष्णु सहाय कमेटी 1954 में और आबिद अली कमेटी 1959 में बनी । उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी ने भी 12 जनवरी, 1961 को एक मीटिंग बुलाई थी । फिर बाद में 13 मार्च को मंत्री जी के ही विभाग के श्री गोविंद राज जी गोरखपुर गये और उन्होंने वहां पर जा कर जांच की । उस के बाद उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा के पार्लियामेंट के मेम्बरों को बुलाकर तथा लेबर लीडरों को बुलाकर एश्योरैंस दिये गये ।

उन एश्योरेंसेज को मंत्री महोदय पूरा करें। उन प्रोसीडिंग्स को देखें और उसके बारे में कार्यवाही करें जिस से गोरखपुर लेबर आर्गेनाइजेशन का रोग न बिगड़ने पाए और एक सेंट्रल लेबर आर्गेनाइजेशन यह हो जिस में एक रिक्रूटमेंट का साधन बन सके और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो भाग है मजदूरों का उस का निर्वहन हो सके।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज में विरोध करने का तो कुछ है ही नहीं। उस का तो मैं समर्थन ही करता हूं। लेकिन इस में प्रस्ताव रखा है कि जो मजदूरों की राशि कोयला खदान वालों के पास पड़ी है उस के बारे में कहा है कि कमीशनर रखा जाएगा लेकिन मैं कहूंगा कि जो नियन्त्रण का साया कानून का अधिकार इस में नहीं है, इस से मेरे मानने नहीं पड़ता।

वास्तविकता यह है कि जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब इस प्रकार हुआ है कि कोयला कुछ सस्ता हो जायेगा और साथ साथ ज्यादा भी उपलब्ध हो जायगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं देखता हूं कि बेगिल्स के जो कारखाने चलते हैं फिरोजाबाद में वहां पर कोयला नहीं मिलता है इसलिए वह बन्द हो गये थे। बाद में सुना है कि कुछ शुरू हुए हैं। मगर अभी भी कुछ कारखाने फिरोजाबाद में ऐसे हैं जिन को कोयला नहीं मिल रहा है और जो उस की वजह से बन्द हैं। इसी तरह चने की भट्टियों को भी कोयला नहीं मिल पाता है। रेलवे से पूछते हैं तो वह कहते हैं कि वेगन नहीं है और वेगन के लिये पूछते हैं तो वह कहते हैं कि कोयला नहीं है, वेगन नहीं है मेरी समझ में यह आता है कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज में कोआर्डिनेशन नहीं है इसलिये इतनी कठिनाई हो रही है। लेकिन साथ साथ उसका असर मजदूरों पर हो रहा है कि उन को मजदूरी का जो पैसा मिलना चाहिये और ऐरियर वगैरह का पैसा मिलना चाहिये वह पैसा नहीं मिलता है। आप ने बताया है क्लाज 4 में कि कमिश्नर रखा जायगा और वह पैसा उन को मिलेगा। जो प्रासीडिंग पढ़ी है उस में कहा है कि करोड़ों रुपय उन का पड़ा हुआ है जो दिया नहीं गया है। उस का कारण यह बताया कि सिर्फ मालिकों का पता नहीं लगता या फिर मजदूरों का पता नहीं लगता। मगर यह जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उस में कहा था कि पैसा कम्पेन्सेशन में से काट कर दिया जायगा। यह भी कहा गया था कि उन की हैल्थ का जो प्रश्न है उस की तरफ भी ध्यान दिया जायगा। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मंत्री जी इस के बारे में बतायें कि हैल्थ के लिए कितने सेंटर खोले हैं, कितने दवाखाने खोले हैं? धनबाद में ऐसी भयंकर परिस्थिति है कि जिस की कोई हद नहीं। वहां मजदूरों की परिस्थिति देख कर ऐसा लगता है कि यहां शासन का नहीं कारखानेदारों का राज है।

इस क्लाज 4 के बारे में मेरा कहना है कि मजदूरों का जो यूनियन्स हैं उन के साथ बैठ कर उन से पूछना चाहिये।

MR DEPUTY SPEAKER: Have you read the Bill very closely?

SHRI R V BADE: I have studied the Bill

MR DEPUTY SPEAKER: But these are things which really do not pertain to the Bill

SHRI R V BADE: I had to say all this during the general discussion. But yesterday nobody knew what was going on in Parliament

MR. DEPUTY-SPEAKER: Even at the first reading, these points are slightly irrelevant to the.....

SHRI R. V. BADE: I will read out Clause 4.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I know what it is. The Bill is to make certain deductions from payments due to coal mines owners and these deductions are towards the payment of arrears to workers.

श्री आर० वी० बडे : इस में कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी जिसे उपधारा (1) मे निर्दिष्ट सभी बकाया या उस का कोई भाग शोध्य हो, कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पश्चात् आयुक्त को ऐसे समय के भीतर जो आयुक्त नियत करे, अपने दावे का सबूत फाइल करेगा।

इस में जो दिया है इन के बारे मे हमारा कोई विरोध नही है।

These are very good clauses. We have no objection. We support them.

लेकिन शासन को जो करना चाहिये, शासन का जो काम है कि कोयला लोगो को सस्ता मिले और आसानी मे उपलब्ध हो वह नही हो रहा है।

What I am saying is, we are not getting coal. The coal has become very dear. As a matter of fact, the coal price has gone up very high. The coal is not available to industry. Wagons are not available.

वह कहते हैं कि वैगन नही मिल रहे हैं, रेलवे का दोष है और रेलवे वाले कहते है कि कोयला खदान वालो का दोष है। कोयला लोगो को मिल नही रहा है। इसलिये मै यह कह रहा हू।

This is the only time to say all this. Therefore, I take this opportunity. As far as the clauses are concerned, we have no objection.

With these words, I support the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call the next speaker, I would like to draw the attetion of the House to the scope of the Bill. The scope is very limited. The first one is to give powers to the Commissioner of Payments to make deductions towards arrears of workers from the payments due to coal mines owners. The second one is to empower the Commissioner of Provident Fund to make claims on behalf of workers. These are the main points. If you confine yourselves to this, then we shall be able to dispose it of expeditiously.

Shri Damodar Pandey.

श्री दामोदर पाण्डे (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मै इस बिल का समर्थन करता हू। सब से पहले जब कोकिंग कोल नेशनलाइजेशन बिल आया था तो उस समय मैं ने सुझाव दिया था कि इस बिल मे इस तरह का प्रावधान रखा जाए कि मजदूरो की बकाया राशि कम्पेन्सेशन मे से काट कर मजदूरो को पहले दे दी जाय और उस के बाद जो पैसा बचे उस मे से दूसरे जो चार्जेज है डेड वगैरह के उन को वसूल किया जाय। उस समय तो हमारे सुझाव को नही माना गया। लेकिन आज इस संशोधन के साथ आए हैं तो मै उन के संशोधन का समर्थन और स्वागत करता हू।

मामला बहुत संगीन है। यह सिर्फ इतने से ही पता चलता है, अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री पाण्डे जी ने आप के सामने रखा कि 26 करोड़ रुपया अकेले सी आर ओ आर्गेनाइजेशन का मालिको के पास है, वह मजदूरों की मजदूरों का पैसा है, उन की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो मालिको के

पास पड़ा है। वह 26 करोड़ है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया। इस के अलावा सरकार के रेकार्ड के अनुसार 11 करोड़ रूपया प्राविडेंट फंड का है तो यह 11 करोड़ और 26 करोड़ सीधे सिर्फ दो एकाउंट में है। इस के अलावा भी बहुत से ऐसे चार्ज है बहुत से ऐसे ट्रिब्यूनल्स के डीसीशंस हैं, बहुत से ऐसे फैसले है जिन में मजदूरों की तनख्वाह के सम्बन्ध में निर्णय किये गये है बहुत से एग्रीमेंटस है जिस में मजदूरों की तनख्वाह के बारे में फैसले है, इस सब की बकाया राशि को अगर एक जगह मिलाया जाय तो यह पता चलेगा कि जितना इन्होंने कम्पेन्सेशन रखा है उस में सिर्फ मजदूरों का बकाया पैसा भी वसूल होने वाला नहीं है।

मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि मजदूरों का जो बकाया बाकी है उस में से कम्पेन्सेशन देने के बाद जो बच जायेगा उस का आप क्या करने वाले है? मै चाहता हू कि इस के संबध मे यह प्रावधान रखा जाय कि इस कम्पेन्सेशन की बकाया रकम में से मजदूरों का जो बकाया है, उसे वसूल करा दिया जाएगा इस के अलावा उन का जो बकाया बच जायेगा, उस पैसे को वसूल करने के लिये सरकार की तरफ से कार्यवाही की जायेगी और उन सब पिछले मालिकों में जो पैसे को हड़प कर बड़े बड़े कारखानेदार बन गये है, इजारेदार बन गये है, कलकत्ता बम्बई और दिल्ली में जिन्होंने बड़े बड़े मकान बनाये है उन मकानों को नीलाम कर के उस पैसे को वसूल किया जायेगा — ऐसी व्यवस्था इस मे होनी चाहिये।

यह जो संशोधन रखा गया है — इस मे थोड़ी खामी अभी भी रह गई है। इस में यह प्रावधान है कि कोल-माइन्ज प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर मजदूरों की तरफ से बकाया राशि वसूल करवायेंगे। यह ठीक है, लेकिन इस में यह भी प्रावधान है कि ग्रेचुइटी की रकम, वैलफेयर फंड की रकम, इस तरह के जितने फंड है, उन की बकाया राशि कोल-माइन्स प्रोविडेन्ट फंड कमिश्नर वसूल करेंगे। लेकिन यह तो एक बहुत मार्जिनल डण् है, इस के अलावा का क्या होगा? बहुत से मजदूरों का बोनस बकाया है, जिस का पिछले सालों मे पेमेंट नहीं किया गया। बहुत से मजदूरों का क्वार्टरली बोनस बकाया है, जो उन की अर्न्ड-कमाई का हिस्सा है, तनख्वाह बाकी है उस 26 करोड़ रुपये का क्या होगा, उस को कहा से लायेंगे, कौन वसूल करेगा। क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि सब मजदूर अलग अलग उस का क्लेम करे? यदि ऐसी उम्मीद करते हैं तो उन मजदूरों का उस बकाया राशि को वसूली करने मे काफी पैसा खर्च हो जायेगा शायद जितना खर्च करेंगे उतना भी वसूल न हो पाये। इस लिये मै चाहता हू कि मंत्री महोदय इस में ऐसा प्रावधान रखें कि सिर्फ मजदूरों को ही अपना वसूल करने का हक नहीं होगा बल्कि जो उन के मजदूर संगठन है, आर्गेनिजेशन्ज है, उन का यूनियनें है, उनको भी वसूल करने का अधिकार होना चाहिये। वे मजदूरों की तरफ से क्लेम दाखिल करें — कमिश्नर के यहा और उस क्लेम पर भी विचार होगा—इस तरह का प्रावधान इस में रखना चाहिये—यह मेरा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, मै अपने को बिलकुल सीमित रखना चाहता था, लेकिन एक-दो सवाल उठाये गये है जिन के संबध मे अगर कुछ न कहा जाये तो अनुचित होगा। अभी कुछ भाइयों ने कहा कि नेशनलाइजेशन हुआ तो कोयला बाजार से गायब हो गया, मिलता ही नहीं है महंगा हो गया है। इस मे कोई द मत नहीं हैं कि कोयले की अवलेबिल्टी कम हो गई है, जिस स्तर तक मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है तथा जिस दर मे कोयला मिलने की

[श्री दामोदर पाण्ड]

हम उम्मीद करते थे, उस दर में नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हुं। सभी कठिनाइयों के बावजूद भी जो मालिकों की तरफ से उठाये गये, उन की तरफ से जो अड़ंगेबाजी हुई, नैशनलाइजेशन को सैबोटाज करने के प्रयत्न किये गये, उस के बावजूद भी आज यह फख़ की बात है कि कोयला खदानों में प्राडेकशन कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी है।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : (मुरेना) इसी लिये दाम बढ़े हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not reallly within the scope of the Bill. It may be an important subject....

SHRI DAMODAR PANDEY: They are making it an issue..

MR. DEPUTY-SPEAKER: We can discuss that on some other occasion, under some other scope.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): What is the benefit to the people? They are stopping cool to houses; they are not supplying to people; prices are rising.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not saying that it is not important. I am only saying that this Bill is not the apprepriate occasion for that

**श्री दामोदर पाण्डे** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वैगन की कमी हुई है—ऐसी बात भी नहीं है, कोयले की की कमी हुई है—ऐसी बात भी नहीं है। वैगन की संख्या भी बढ़ी है और कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है—यह इस बात से साबित हो जायेगा कि देश की डिमांड के मुताबिक जितना भी कोयला इस साल मूव हुआ, उतना कोयला पहले कभी देश को नहीं मिला... (व्यवधान)

**श्री हुकम चन्द कछवाय**: इतना महंगा कभी नहीं हुआ जितना अभी है।

**श्री दामोदर पांडे** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर विशेष कुछ न कह कर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संशोधन रखे गये हैं सरकार की ओर से, वे स्वागत योग्य हैं, इन को हर तरह की तरजीह मिलनी चाहिये हर तरह का बढ़ावा मिलना चाहिये। जैसा मैंने सुझाव दिया है कि कम्पैन्सेशन के बाद जो बकाया रकम रह जायेंगी—उस के सम्बन्ध में मैं मंत्री जी के विचार जानना चाहूंगा। इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये आप क्या व्यवस्था करना चाहेंगे? दूसरी बात—मजदूर संगठनों को क्लैम देने का अधिकार दिया जाये उस के सम्बन्ध में मंत्री जी का निश्चित मत क्या है, वह भी यहां रखें।

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem): Hon. Mr. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of my party DMK, I would like to say a few words on the Coking and Non-Coking Coal Mines (Nationalisation) Amendment Bill, 1973. Today the country is facing crisis arising out of shortage and scarcity in the availability of steel and coal. In the coal industry we find that demands of the mine workers are not being met to their satisfaction. At this critical hour the nation was shocked by the unfortunate death of Shri Mohankumaramanglam who was heading the Ministry of Steel and Mines. The entire country was watching apprehensively as to who would take charge of the Ministry of Steel and Mines. The nation was also afflicted with the problem of black marketing in coal and the poor people were being put to great hardship as a result. To the relief of the people of Tamilnadu and the entire country, Shri T. A. Pai was chosen to take the responsibility of running this vital economic Ministry. Shri Pai, as ex-Minister of Railways is fully aware of the fact that more than 500 trains are not running today as a result of coal shortage. Now that he has assumed the charge of

*The original speech was delivered in Tamil.

Ministry of Steel and Mines, it is our fond hope that he would be able to find ways and means to tide over the crisis due to shortage of coal.

Much as I would like to speak, I know that hon. Deputy-Speaker would not permit me to make elaborate submission as we have clause by clause consideration now. Therefore, I propose to confine myself to a few specific issues.

This amendment bill has come before the House just because there were misdescriptions in relation to the particulars of coal mines in the Nationalisation Act It is indeed surprising that such a situation should have come about when the Ministry of Steel and Mines had all the data in relation to mines in their possession The Ministry has a large number of highly paid officers and also middle level officers. Inspite of this we find that at the time of drafting the Nationalisation Act correct and verified information was not given to the Minister with the result today the House is discussing this Amendment Bill. I would therefore ask the hon. Minister what action he proposes to take against the officers responsible for this kind of situation in which the Ministry has been placed.

Sir, at the time when the Nationalisation Bill came up for discussion in the House, it was pointed out by many hon. Members belonging to both opposition and ruling parties that arrears to the Provident Fund due from the coal mine owners were running into several crores. Shri Matha Gowder, a member belonging to my party emphasised the need to make a provision in the Bill providing for the deduction of the arrears of Provident Fund, Gratuity and Pension due to workers from the compensation proposed to be paid to the mine owners. This demand was also made by all sections of the House. Had the Government accepted this suggestion of the members and shown respect to the feelings in the House, we would not be discussing an amendment Bill of this nature. On 22nd March, 1973 in reply to question No. 59, Shri Raghunatha Reddy, the Minister for Labour and Employment stated that the arrears from the mine owners to the Coal Mines Provident Fund were as much as Rs. 11.76 crores as on 30th September, 1972. The Annual Report of the Ministry of Labour and Employment has mentioned that as many as 1505 cases are pending against the coal mine owners for the recovery of Rs. 6.70 crores as P.F. Arrears I would like to know from the hon. Minister as to the fate of these cases. Will the Government continue the cases acting on behalf of the coal mine workers?

Sir, I would now like to refer to another issue Government are fully aware that many coal mine owners did not implement the various recommendations by the Wage Board for coal mine workers and large number of coal mine workers were denied their legitimate wages. I would like to know what action is proposed against the coal mine owners who did not implement the Wage Board recommendations.

Sir, at the time of nationalisation we were all proud of the fact that this national and socialist Government were are taking right steps towards bringing in socialism and many hopes and expectations were raised in the minds of the people of the country. But we found later that the nationalisation of coal mines was not total and in fact a few specific mines were left out in the hands of the Private Sector. I do not know whether the hon. Minister is fully aware of this. I do not want to be misunderstood that I am trying to criticise the decision of late Shri Mohankumaramanglam for whom I have the higest regard and who was a personal friend belonging to my district. However, Sir, till this day I am unable to appreciate the exact reasons that led the Government to decide to leave out of the scope of nationalisation, a few specific mines I would like to ask the hon. Minister the rationale behind the decision to leave these mines untouched by Government. Sir, I am unable to go into details as it is not a general discussion that is taking place now.

Sir, if the Government had taken the views of the members and the suggestions made by them regarding the need for provision in the Nationalisation Act for

[Shri E. R. Krishnan]

deduction of the arrears due from the coal mines owners to the Provident Fund etc., seriously we would not be spending the time of the House to discuss a Bill which now seeks to provide just for this. I would also repeat that action should be taken against the officers who were responsible for the errors, omissions and misdescriptions that are found in the Nationalisation Act necessitating this Amendment Bill. In the end, Sir, I would appeal to the hon. Minister to ensure that there is no shortage of coal leading to all kinds of evils like black marketing, profiteering and so on. A Government which describe themselves as a socialist Government should not hesitate in bringing total nationalisation of all coal mines If they fail to do so it is but natural for the people to view the Government with suspicion.

With these words I conclude

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA (Balasore): This discussion on this amendment brings to our mind the saga of untold suffering of millions of coalminers in this country If I count all right more than 157 fictions have been written about these dumb driven cattle who surround the coalmines of this country. There are over 731 coalmines employing 1.50 lakhs workmen in coalmines. About compensation to mineowners it strikes me how is it possible that those who sucked the blood of the coalminers for 18 years in this country should be given any compensation. We have preferred to give them compensation. Ours is a democracy and we have to look at both sides of the picture and so we have preferred it. We have to consider these millions of human ghosts painted in black roaming round the coalmines but these people do not get any sympathy from any quarter far less from the Government.

I have gone through the books by Sir Thomas Holland, Sir Lewis Fermez and Sir Cecil Fox who have analysed in detail about the procedure of coalmining and how to develop it. It was in 1939 that the Coal Mines Committee decided that the Government should nationalise it. The State must go in for acquisition of coalmines. I must thank the late Shri Kumaramangalam for this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are not discussing the nationalisation of coalmines.

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: I am just doing a flash-back. The Commissioner for Provident Fund has now been empowered to deduct money from the wages of workers for provident fund, gratuity, pension and other purposes which have been established for the welfare of workers. I would have preferred no appeal to any court of law against any decision of this Commissioner. But, unfortunately, the Government has preferred it again, probably, in the sense of a democratic principle

Well, Sir, there is a Commissioner for Provident Fund who is now empowered to take up the cases of the workers. But, I support the standpoint of Shri Damodar Pande who said that even the Unions should take up the cases of the workers. my friend, referred to Gorakhpuri workers I have seen with my own eyes the sad tale of the Gorakhpuri workers not only in mines but also in steel plants in other areas. You will find a Gorakhpuri worker just like a cattle with no clothes and nothing to wear or nothing to eat even. He becomes a victim. The word 'Gorakhpuri worker' is seldom used in the name of a working-class in the whole of the country. One has to consider the ameleoration of the grievance of the Gorakhpuri workers as to how to get the money which is due to them.

Sir, the safety of the coalminers in mines is beyond description. There is no safety. There is a National Council for Safety and Mines which is patterned on the National Council for Safety in Great Britain. I would just like to bring to the notice of the Hon. Minister one thing. That is about the safety of the coalminers. Unfortunately this organisation had not been developed for one specific reason. This organisation did not consist of publicity experts. They are all mining experts

only. I request the hon. Minister to have this organisation on the pattern of a publicity organisation and not as a branch of the Director General of Mines Safety.

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : उपाध्यक्ष जी, कोकिंग कोल और नानकोकिंग कोल के सम्बन्ध में जो संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका स्वागत करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा कि इसमें कुछ खामियां हैं लेकिन इसके बावजूद इसमें कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों को सहायता मिलेगी, इस दृष्टिकोण से ही मैं इसका स्वागत करता हूं। अपने संशोधन को पेश करते हुए उस पर बोलने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। श्री एन०एन० पांडे ने जिस बात का यहां जिक्र किया, गोरखपुर में जो लेबर सेंटर है उसको उठाने की जो चर्चा चल रही है उसका उन्होंने जो विरोध किया वह ठीक विरोध किया, मैं भी उसका विरोध करता हूं। मेरा एक ही निवेदन है कि स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम जी ने जो आश्वासन दिया था कि इस कारखाने को फिर से संगठित करके चलाने की कोशिश की जायेगी उसका पूरा पूरा पालन किया जाये। अब मेरा जो संशोधन है क्लाज 4 के आखिर में वह इस प्रकार है :

**Page 3,—**

*after* line 19, *insert*—

> "12B. At every mine, colliery and also at Board of Directors' level there shall be elected representatives of the workmen who in addition to jointly working after the management of the nationalised mines will help the management to scrutinise the workers' claims on previous owners on account of wages, provident fund, gratuity, earned leave wages or any other such claims before referring to the Commissioner."

यह बहुत ही आवश्यक संशोधन है, और मैं चाहूंगा कि सदन के तमाम सदस्य तो इसका समर्थन करें ही, सरकार भी इसको स्वीकार कर ले। इसमें दो बातें कही गयी हैं और यह मांग की गई है कि आप वर्कर्स के प्रतिनिधि को चुनाव के जरिये नियुक्त करें ताकि जो मालिकों पर पुराना बकाया है उसकी वह छानबीन करें। कमिश्नर के पास दावा करने से पहले सरकार और मजदूरों के प्रतिनिधि मिलकर के छानबीन कर लें ताकि कोई गड़बड़ी न रहने पाये, तब प्रॉवीडेंट फंड कमिश्नर के सामने दावा पेश किया जाय। अगर आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो कोई चीज नहीं छूट पायेगी, और मजदूरों को कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि उनके प्रतिनिधि उसमें रहेंगे। हर लेविल पर हर खान में, ऊपर डायरेक्टर लेविल तक, ऊपर से नीचे तक इस तरह का अधिकार आप मजदूरों को दें उनके प्रतिनिधियों को शामिल करें ताकि खान मालिकों पर जो मजदूरों का बकाया है, जो उन्होंने लूट की है, वह उनसे वसूल किया जा सके और जरूरत पड़ने पर मालिकों की सम्पत्ति का नीलाम करके उस बकाया को वसूल किया जा सके। हम रिप्रेजेन्टेटिव कैरेक्टर इसलिये देना चाहते हैं कि आज जो कोकिंग कोल कोलियरी या नान-कोकिंग कोल कोलियरी में गड़बड़ चल रहा है, उत्पादन में जो कमी हुई है इसे रोका जाय। अभी पांडे जी ने कहा कि उत्पादन बढ़ा है, जबकि मेरे सवाल के जवाब में आपने 26 जुलाई को कहा है कि

> "There has been a marginal fall in production of coking coal after take-over of the mines by the Government.".

तो पांडे जी का कहना यहां सही नहीं है। मैं कि मैं राष्ट्रीयकरण का समर्थक हूं लेकिन मैं समझता हूं कि आप के गलत व्यवहार के कारण ही प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो रही है। फिर मैंने एक सवाल किया था अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन चार महीनों में प्रोडक्शन की क्या फिगर्स हैं ताकि हमें मालूम हो कि सचमुच में कमी मार्जिनल है या ज्यादा है। जहां तक मेरी जानकारी है 40 परसेंट तक कहीं कहीं उत्पादन में कमी हुई है। लेकिन आपने जवाब क्या दिया है :

[श्री रामावतार शास्त्री]

"Information is being collected and will be laid on the Table of the House."

21 दिन पहले नोटिस दिया और आप यह पता नही लगा सके । इस का मतलब है कि कही दाल मे काला है जिस की वजह से आप सही बात नही बताना चाहते हैं । तो उत्पादन मे कमी हुई है । उस को दूर किया जाय, और जिन कारणो से उत्पादन मे कमी हो रही है इस के लिये आप के अधिकारी और आप की व्यवस्था जवाबदेह है ।

कोयला निकालने के साधनों का अभाव है, आप का कोई अधिकारी पिट मे नही जाता कि फेस, हो रहा है कि नही हो रहा है कोयला काटने के लिए फेस बनाना पडता है । टोपी की बत्ती है कि नही, गैंता है कि नहीं कोयला काटने के लिये, पर्याप्त टबों और लाइन की व्यवस्था है या नही । इन सब चीजो का अभाव है । मजदूर तो चाहता है कि कोयले का उत्पादन बढे, लेकिन आप के यहां साधनो की कमी है । इतना ही नही, वहा के अफसर बारबार माग कर रहे हैं कि ठीक से उत्पादन बढे, इस के लिये हर कोलियरी म एक ही यूनियन रहे । लेकिन आप ध्यान नहीं देते पार्टीबाजी करते हैं । आप एक यूनियन बनाइये और जो सचमुच मे प्रतिनिधि मूलक हो उस को मान्यता दीजिए फिर चाहे वह आई०एन०टी०यू०सी० के साथ हो, या आई०टी०यू०सी० या हिन्द मजदूर सभा के साथ हो, या किसी अन्य के साथ हो ।

इसलिये मेरे सशोधन मे दोनो बाते कही गयी हैं कि हम उत्पादन कैसे बढा सकते हैं । इस पर आप विचार कर सकते हैं । आप मजदूरो के प्रतिनिधियो को शामिल करे और जो मजदूरों का बकाया खान मालिको पर है उ को लिया जाय । जनरल कारखानों के लिये प्रौवीडेंट फड कमिश्नर अलग है और कोल माइन्स के लिये अलग है । मेरा सुझाव है कि दोनो को एक कर दें और तमाम कर्मचारियो को जनरल प्रौवीडेंट फंड कमिश्नर के यहा ट्रासफर कर दें और सब मिल कर के काम करे, और काम आसानी से चले ।

अन्त मे मैं पुन निवेदन करूंगा कि आप मेरे सशोधन को स्वीकार कर लें ।

**श्री राम सिंह भाई वर्मा** (इदौर) . उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हू । मुझे दुख इस बात का है कि जो सही बात शासन के सामने रखी जाती है सदस्यो की तरफ से तब तो सरकार स्वीकार नही करती , और दूसरे ही दिन सदन मे आकर खडे हो जाते हैं और कहते है कि यह हमे करना है । पिछले अधिवेशन मे जब कोल माइन के राष्ट्रीयकरण का बिल आया तो मेरा यह सशोधन था कि मुआवजे की रकम, मजदूरो की जो बकाया है उस को काट कर, मुआवजा देना चाहिये । लेकिन मत्री जी ने स्वीकार नही किया । लेकिन दूसरे ही दिन सरकार ने अपना वही सशोधन पेश कर दिया । यह देख कर हमे बडा दुख होता है ।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकरण करने के साथ, आना पाई के साथ साथ और भी जो वसीयत आपको मिली है उन का भी सारा दायित्व सरकार के ऊपर चुकाने का आता है । अभी सी० आर० ओ० की 26 करोड रकम निकलती बतायी , 10, 11 करोड रु० प्रौवीडेंट फड का देना है, और इतनी ही रकम कोल बैलफेयर फड की होनी है, जो सब मिला कर के 50 करोड रु० के बैठती है । इतनी रकम मुआवजे की नही होनी । जिन कानूनो का पालन खान मालिक लोग नही करते आये हैं और जो कानून सरकार ने बनाये हुए है, राष्ट्रीयकरण के बाद अगर सरकार उन का पालन नही करती है तो इस से बुरी बात और क्या हो सकती है, और अब उन कानूनो का पालन कराने मे ही सरकार को कितने करोड रु० खर्च करने होगे वह मैं कहना चाहता हूं । वर्षो तक मजदूरो के शोषण से यह कोलमाइन्स चलायी जाती रही हों और शासन का ध्यान उनकी तरफ न जाय, यह बडे दुख की बात हैं ।

आप ने प्रोडक्शन की बात कही है, कितनी कोलमाइन्स क्रीएट की गयी हैं, खर्चा किया गया है उस के परिमाण मे आज उत्पादन नही है, बल्कि उत्पादन घटा है, और ऐम्प्लायमेंट मे भी कमी हुई है। क्यो कि प्रोवीडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनस, वेलफेयर फंड आदि देना पड़ता है इसलिये ऐसे श्रमिक खान मालिकों ने रखे जिन का रजिस्टर मे नाम ही नहीं है और जेब मे चार रु० की जगह दो रु० निकाल कर उन को देते रहे है। आप की माइन्स की आज क्या हालत है, मशीनरी की क्या हालत है? उनका ठीक मेंटेनेंस तक नही है। ऐम्प्लायमेंट मे तो कमी हुई है साथ ही ऐक्सीडेंटस मे भी वृद्धि हुई है, कारण यह है कि सेफ्टी माइन्स का पालन नहीं किया गया। 1958-59 मे जो वह तय किया गया कि सेफ्टी के लिये अमुक अमुक चीजें श्रमिकों के लिये होना चाहिये कानून के तौर पर, उन का आज तक पालन नहीं हुआ है।

दुनिया के कुछ देशो मे मैंने कोलमाइन्ज का अन्दर जा कर देखा है। उनको देख कर फख्र का अनुभव हुआ है उनकी सुन्दर वर्किंग कंडीशन्स के लिये। लेकिन हमारे अपने देश मे कोलमाइज की जो दशा है उसको देख कर शर्म आती है। जो आवश्यक वस्तुए मजदूरो को जब वे माइज मे जाते हैं सेफ्टी के लिये मिलनी चाहिये नही मिलती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER Can you enlighten me in which way this comes within the scope of this Bill? Please explain that.

श्री राम सिंह भाई वर्मा : पैसे की बात कर रहा हू। यह ठहराया गया है कि माइन्स के श्रमिकों के लिये बूटो के लिये फारेन एक्सचेंज का इतजाम किया जाएगा। लेकिन 1958-1959 से 1973 तक नही हुआ। आज कोल माइज वर्कर्ज को जूते नही मिले हैं जो कानून के द्वारा उनको सेफ्टी के लिये मिलने चाहिये थे। कोलमाइज के मालिको ने वे उपलब्ध नही किए। ये जो सब चीजें हैं इनके ऊपर राष्ट्रीयकरण के बाद आपको विचार करना चाहिए। वर्कर्ज को जो सुविधाये दी जाती है वे समान रूप मे सबको मिलनी चाहियें, यूनिफार्म भी देनी चाहिये। कानून लागू होने चाहियें और सेफ्टी के वास्ते जो चीजें आवश्यक हैं वे उनको दी जानी चाहिये—

MR. DEPUTY-SPEAKER Even if it is a general discussion, it does not come within the scope of this Bill. Please come to the scope of the Bill

श्री राम सिंह भाई वर्मा वेलफेयर की बात कर रहा हू।

MR DEPUTY-SPEAKER This is about empowering the Commissioner to make payments, to make certain deductions towards the payment of arrears About the improvement of the working conditions of the workers, though it is important, there should be another occasion for it, not within this Bill. That is what I am saying.

श्री राम सिंह भाई वर्मा आज नहीं आठ दिन पहले जब यह एजंडे पर आया था तब मैंने अपना नाम दिया था। सर्वप्रथम मेरा नाम है। आप इस बिल को सरकाते चले गए। आपने फर्स्ट रीडिंग होने नही दिया और हमे बोलने का मौका नही दिया। इसकी जवाबदारी किस की है। नाम मेरा सब से पहले लिखा हुआ है।

MR. DEPUTY-SPEAKER I am not denying your opportunity. I am only talking about the relevance You might have given your name a fortnight ago. But how is it relevant to the scope of the Bill? There should be a limit

श्री राम सिंह भाई वर्मा मिनिस्टर साहब नए आए हैं। उनके ध्यान मे मैं कुछ बाते लाना चाहता हू। कोलमाइज के मालिक

(श्री राम सिंह भाई वर्मा)

ने श्रमिको का बहुत शोषण किया है । पैसे के साथ साथ दूसरी तरह का शोषण भी किया है । पैसा तो मामूली बात है, छोटी बात है लेकिन एक्सीडेंट जो हो रहे है जानें जा रही हैं, वे बहुत बुरा बाते है । उनको रोका जाना चाहिये । छतें गिरने से, दीवालें गिरने से ये हो रहे हैं । उनको रोकने के लिए यह कहा जाता है कि टिम्बर की जरूरत है किन्तु लकड़ी नही मिल रही है । लकड़ी नही मिल रही है इस वास्ते क्या मजदूर मरते जाए ? इसके लिये फोरेस्ट रिजर्व कर प्लाटेशन करिये । मजदूरो की चिता के ऊपर रोटी सेकना कोई अच्छी बात नही है ।

दूसरी बात यह है कि जैसी और डस्टी माइज के अन्दर रोशनी की खास जरूरत होती है । दूसरी रोशनी हो नही सकती । कानून मे यह कहा गया है कि इलक्ट्रिक लैम्प दिये जायेंगे श्रमिक को । लेकिन कही भी खदानो मे नही दिये गये है और जो नाम मात्र के लिए दिए भी गए हैं उनका उपयोग नही हो रहा है । खराब हालत मे हैं । कमिशनर को अधिकार आप दे रहे है । लेकिन मेरा कहना है कि कोलमाइज के अन्दर जो प्राविडेंट फड कमिशनर हैं उन्हाने यह सारा चौपट किया है । अगर वे चाहते तो इतनी रकम बकाया जमा हो क्यो होने देते ? आज आप पावर दे रहे हैं, अच्छी बात है । लेकिन अपील का प्रावधान आप करे । यह नही किया तो फिर लापरवाही होगी जिस के बारे मे हम हाउस मे चिल्ला रहे है और आप चालने नही दे रहे । पैसे के दायित्व मे बडा जान का दायित्व होता है । इस वास्ते पहले आप सफ्टी का इन्तजाम करें । पैसा आप कुछ कम दे दे इसकी कोई चिन्ता नही है ।

**श्री धनशाह प्रधान** (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, कोकिंग तथा नान-कोकिंग कायला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1973 जो पेश हुआ है इसका मैं समर्थन करता हूं । 1972 मे हमने जो कानून पास किया था उस मे कुछ कमियां रह गई थी । उनको दूर करने के लिए इस विधेयक को यहां लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हू कि अगर पहले से ही उन कमियो की तरफ ध्यान दिया जाता तो इस संशोधन को लाने की आपको जरूरत नहीं पडती । पहले वाले बिल मे ही इन सब की सफाई कर दी जानी चाहिए थी। मालिकों के ऊपर 11 करोड 76 लाख रुपया श्रमिकों का प्राविडेंट फड का बकाया है । वह रिकवर नही हुआ है । इसको पहले ही आपको साफ कर देना चाहिये था । यदि आपने ऐसा किया होता तो इतना श्रम और समय खर्च न करना पडता जो अब करना पड रहा है । मालिकों ने मजदूरो की भविष्य निधि की रकम काट करके अपने लिए खर्च कर ली है । इसकी वसूली के लिए कमिशनर की नियुक्ति की जा रही है । इसका मैं स्वागत करता हू । राष्ट्रीयकरण का पहले बिल पास करते समय इन बातो पर विचार नही किया गया और अगर विचार किया जाता तो आज यह बात न होती ।

खानो के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन कम हो रहा है । मजदूरों मे उत्साह की भी कमी दिखाई दे रही है इस वास्ते उनके कल्याण कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । साथ-साथ कोयले की कीमते भी निर्धारित की जानी चाहिये ताकि सभी लोगो को उचित दामों पर कोयला मिल सके और इसकी व्यवस्था भी आप को करनी चाहिये । ऐसा देखा गया है कि जिस किसी चीज का राष्ट्रीयकरण किया जाता है वह चीज बाजार से गायब हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है, फिर चाहे अनाज हो, कपडा हो,कोयला हो या कोई दूसरी चीज हो । मैं चाहता हू कि यह जो चीज है इसकी ओर आपका विशेष ध्यान जाए । कोयला उचित दामो पर मिले । ऐसे उपाय भी काम मे लाए जाए ताकि जनता का उत्साह और विश्वास राष्ट्रीयकरण के प्रति बना रहे ।

**श्री राम नारायण शर्मा (धनबाद)** : कोकिंग और नान-कोकिंग कोलमाइंज नेशनलाइजेशन बिल का जो संशोधन विधेयक रखा है इसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। कोयला खदानों के मजदूरों को इस विधेयक ने एक राहत की सांस दी है और जो चिन्ता 1972 और 1973 में राष्ट्रीयकरण के समय उन लोगों को थी वह चिन्ता आज कुछ कम हुई है। बात असल में यह है कि वर्कर्ज को इ नों की इतनी बड़ी रकम ड्यू है कि कम्पेंसेशन सारी रकम देने पर भी वह पूरी नहीं होगी।

**15.00 hrs.**

जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, मालिकों पर 11.67 करोड़ रुपये केवल प्राविडेंट फंड के ड्यू हैं। अभी माननीय सदस्य, श्री एन०एन० पांडे ने बताया है कि सी० आर० ओ० के लोगों के—गोरखपुरी लेबर के—26 करोड़ रुपये ड्यू हैं। इसके अतिरिक्त एक हजार कोलियरीज में से बहुत से कोलियरी वालों ने मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दी, उनको महंगाई भत्ता नहीं दिया, उनको छुट्टी के पैसे नहीं दिये और जो दो बोनस हैं, उनकी भी बहुत सी रकम बाकी है।

अगर हम इस सारी रकम का योग करते हैं, तो वह 100 करोड़ रुपये के आसपास होती है। कोकिंग कोल के मालिकों का मुआवजा 16 करोड़ रुपये तय हुआ है और उससे दुगुना मुआवजा नान-कोकिंग कोल के मालिकों का तय हुआ है। इस तरह अगर मुआवजे की कुल रकम भी मजदूरों के ड्यू में ले ली जाये, तो उससे मजदूरों के ड्यूज में से आधे की ही अदायगी हो सकती है। अगर हम फैमिली पेन्शन, ग्रेच्यूइटी और वेलफेयर आदि बातों को भूल भी जायें, तो भी वह रकम पूरी नहीं होती है।

हां, पहले तो मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलने जा रहा था, क्योंकि उस समय हमारे पर्सवेशन के बावजूद सरकार ने हमारे संशोधनों को स्वीकार नहीं किया था। अब सरकार उस बात को दूसरे रूप में लाई है, यह स्वागत की बात है।

प्राविडेंट फंड के ड्यूज, जो 11.67 करोड़ रुपये हैं, कलेक्ट करने की जिम्मेदारी प्राविडेंट कमिश्नर को दी गई है। लेकिन चार लाख वर्कर्ज के बाकी सब ड्यूज को भी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी अगर प्राविडेंट फंड कमिश्नर पर डाल दी गई, तो उसका परिणाम यही होने वाला है कि अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं हो सकेगी और उनका दावा ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनको अपने ड्यूज को कलेक्ट करने का ज्ञान ही नहीं है। जब तक सरकारी मशीनरी उन लोगों की सहायता नहीं करेगी, तब तक इस प्रावधान के बावजूद उनको जो राहत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल सकेगी।

मैं मंत्री महोदय के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तो प्राविडेंट फंड की रकम को वसूल करे। मजदूरों की संस्थायें मजदूरों के अन्य ड्यूज को वसूल करने में सहायक हों और जहां ऐसी संस्थायें नहीं हैं, वहां, चूंकि अब सब मजदूर सरकार के अन्तर्गत आ गये हैं, सरकारी स्टाफ उनकी मदद करे, उनको जानकारी दे और उन के दावों को क्लेम कमिश्नर के सामने रखे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि इस विधेयक के द्वारा सरकार उन मूक मजदूरों की मदद करना चाहता है।

मैं इस विषय के एक और पहलू की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जब यह कहा जाता है कि कोयला खदानों में उत्पादन कम हुआ है, तो उसके उत्तर में कहा जाता है कि हमको गाड़ियां नहीं मिलती हैं, जिससे कोयला मव नहीं हो

[श्री राम नारायण शर्मा]

पाता है, और हमको पावर नही मिलती है, जिनसे हम उत्पादन नही कर पाते है । पावर की कमी के सम्बन्ध मे मिनिस्ट्री आफ पावर कहती है कि हमको कायला नही मिलता है । इसी तरह रेलवे विभाग भी कहता है कि हमको कायला नही मिल पाता है । इस अवस्था मे आज देश मे एक औद्योगिक तनाव पैदा हो गया है और सब लोग दूसरो पर जिम्मेदारी डाल कर अपनी अपनी जिम्मदारी से मुक्त होना चाहते है ।

लेकिन मै सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हू कि सरकार की तो सम्मिलित जिम्मेदारी है । कोयला उत्पादन की विभागीय जिम्मदारी श्री पाई की हो सकती है, पावर के लिए डा० के० एल० राव की जिम्मेदारी हो सकती है और रेलवे को चलाने के लिए श्री एल० एन० मिश्र की जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन इन सबकी सम्मिलित जिम्मदारी भी है और वह जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है । आज सब उद्योगो मे एक तहलका सा मचा हुआ है । छोटे उद्योग चलाने वाले भी बेचैन है । सरकारी अधिकारी अपनी अपनी जिम्मदारी को समझ नही पाते है । जैसे और सार्वजनिक उद्योग टाप-हैवी हो चुके है, वैसे ही कोयले के नैशनलाइजेशन के बाद नान-कोकिंग कोल माइन्ज एथारिटी और भारत कोकिंग कोल इन दोनो आर्गनाइजेशन्ज की टाप-हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होती जा रही है । अब भी अपने अपने सम्बन्धियो और भाई-भतीजा का रिक्रूट करके एडमिनिस्ट्रेशन का टाप-हैवी बनाने का काम अनवरत चल रहा है । इस प्रकार इन सस्थाओ की हालत भी वही होने जा रही है जो अन्य सार्वजनिक सस्थाओ की है । अगर इस सम्बन्ध मे तत्काल सावधानी न बरती गई, तो सार्वजनिक क्षेत्र की और भी बदनामी होने वाली है ।

इन शब्दो के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हू ।

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): Sir, I welcome the Bill and support the amendments sought to be incorporated by this Bill When the main Bill was being considered in this House in 1972, a Member of this House, Shri Chatterjee, had tabled an amendment But Government did not accept it This Government, this power-drunk government, this power arrogant government, do not hear any constructive suggestions put forward by the opposition That is the position

Section 4 provides for the transfer of title in respect of interest bonus wages etc to the Central Government as specified in the First Schedule in relation to coking coal mines Section 5 provides that the right, title and interest of the owners of the coke oven plants specified in the Second Schedule shall vest in the Central Government Section 12 provides for the payment of an amount

In Schedule I of the principal Act column 5 specifies the amounts in rupees to be paid by the Government to the owners of the mines During the debate on the main Bill we had raised this question and expressed our doubt that this amount has not been determined or fixed on any scientific formula or based on any rational data, and that the amount is determined arbitrarily according to the sweet will of the Government They have favoured the foreign-dominated companies At that time, late Mr Mohan Kumaramangalam had categorically stated that the position is not likewise but it is otherwise I would like to quote him

MR DEPUTY SPEAKER You are re-opening the question of amounts fixed

SHRI P M MEHTA I am not re-opening the question The First Schedule specifies the amount What I want to bring to the notice of the House and to the notice of the Minister is that they have not kept the assurance given by late Mr Mohan Kumaramangalam, the Minister in charge Not only that They have given handsome amounts to their favourites who have paid large sums to the election fund of the ruling party

MR. DEPUTY-SPEAKER: If this is not re-opening the question, how does it come within the scope of this Bill?

SHRI P. M. MEHTA: It comes within the scope of the Bill. Section 4 provides for transfer of powers

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have not been able to follow how it comes within the scope of the Bill. I am a little sluggish in my brain power. I will listen to you a little more.

SHRI P. M MEHTA: Unless the amount is properly paid, how can the deduction take place? At the end, the worker will be the sufferer.

This is what late Mr Mohan Kumaramangalam had said:

> "We have proceeded on the basis of the valuation of the physical assets of the local coal mines on the one side and the valuation of stores and stocks on the other. We have made a valuation of this and on that basis fixed a reasonable amount is compensation I do not think there is any difficulty We have not proceeded on the basis of the paid-up capital or the loans but purely on the basis of the valuation of the physical assets of each mine"

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can only summarise what he had said. Even so, I have not been able to understand how it comes within the scope of the Bill.

SHRI P. M. MEHTA: As I have quoted him, he had assured the House that amount will be calculated on the basis of physical assets.

What has this Government done? They have given to Bundhemo, compensation amounting to Rs. 23.32 lakhs against their assets of Rs. 15 lakhs.....

MR. DEPUTY-SPEAKER I must tell you, all this is irrelevant to the Bill.

SHRI P. M. MEHTA: It is relevant.

MR. DEPUTY-SPEAKER: How is it relevant to the question of giving power to the Commissioner of Payments to make these deductions towards the arrears of workers? How do the amounts come in now? I do not understand it

SHRI P. M. MEHTA Here, Clause 4 says:

> "After section 12 of the Coking Coal Act, the following section shall be inserted, namely, 12A."

What is section 12 of the principal Act? It says:

> "In consideration of the retrospective operation of the provisions of section 4 and section 5, there shall be given by the Central Government in cash to be owner of every coking coal mine specified in the First Schedule..."

Therefore, it is relevant. Any way, I will finish in two minutes..

MR DEPUTY-SPEAKER You are going into details of how much amount was given to each owner and so on. This is irrelevant Any way, you have limited time and you try to conclude now.

SHRI P M MEHTA: I will finish in two minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are going into details of amounts given to each owner now. I do not think that has anything to do with the power given to the Commissioner of Payments.

SHRI P. M. MEHTA: I will only read out the percentages of compensation given against assets.

Burrdhemo—155 per cent; Benjaneohari—29 per cent; Khas Jambad—6 per cent; Hingir Rampur 60 per cent, Swadeshi Mining 54 per cent, Newtonchikli East Nimcha Madhajore 125 per cent; this K. Worha Group have paid a handsome amount in the Dindigul elections to the ruling party....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not dispute your right to criticise the ruling party or the Government, but there should be a proper occasion The scope of this Bill does not cover all that.

SHRI R. K. SINHA (Faizabad): Sir, shall we be allowed to have any discussion at all on planning—planning for the poor people of India? We could not discuss it in the last Session This Session is also coming to a close. Planning is taking a back seat.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please.

SHRI P. M. MEHTA: Shethia Mining 13 per cent, Bengal Coal 73 per cent Western Bengal Coal Fields 52 per cent and Parasea 25 per cent I would ask the Minister to scrutinise all these things. Sir, after nationalisation. . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him scrutinise.

SHRI P. M. MEHTA: After nationalisation what has happened to these industries? The production has dropped....

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is also not within the scope. Mr. Madhu Limaye.

SHRI P. M. MEHTA: The prices have gone up and workers problems are accumulating....

MR. DEPUTY-SPEAKER: There may be another occasion for all that. Mr Madhu Limaye.

SHRI P M. MEHTA: ..and the Management has not attended to their problems.

श्री मधु लिमये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक मन्त्री महोदय यहा क्यो ले आए ? अगर पहले विधेयक पास करते समय सोच समझ कर काम किया जाता तो यह नौबत नही आती । लेकिन एक अरसे से मैं देख रहा हूं कि राजनैतिक प्रचार के लिए ये लोग जल्दी जल्दी राष्ट्रीयकरण के कानून यहां पर पास कर रहे हैं और जब हमारे द्वारा यह कहा जाता है कि इन कानूनों को अध्ययन करने के लिए इन को प्रवर समिति या सयुक्त समिति के पास भेजा जाय तो ये लोग विरोध करते है । इतनी बडी भूल और कमी इस विधेयक मे रह गई । हमारे स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मगलम के साथ इसके बारे मे मेरा पत्र-व्यवहार हो रहा था । लगातार मजदूरो की यूनियन्स के पत्र आ रहे थे कि राष्ट्रीयकरण का विधेयक पास हो गया लेकिन इनको पता ही नही है कि कोल इडस्ट्री में हालत क्या है ? राष्ट्रीयकरण करने के पहले क्या कोल इडस्ट्री की समस्याओं का पूरा अध्ययन इनको नही करना चाहिए था ? मजदूरो की तकलीफे क्या हैं ? इस तरह का इन लोगो ने कोई अध्ययन नही किया । नतीजा यह हुआ कि इन्होने मुआवजे की रकम तय करने के बारे मे जो प्रावधान पास किया तो उसमे इसके सबध मे कोई व्यवस्था नही थी कि मजदूरो का जो पचासो किस्म का बकाया पड़ा है—वेतन का बकाया, प्राविडेंट फड का बकाया, बोनस का बकाया, इन सारे बकायो का क्या होगा ? इसके बारे में इन्होने कोई इनजाम नही किया ।

तो पहले मैं इसके ऊपर आपकी व्यवस्था चाहता हू कि इन लोगो का यह जो तरीका है जिसके चलते इन कानूनो मे कमिया रह जाती हैं, क्या इस सदन मे आप यह व्यवस्था दगें कि जो भी महत्वपूर्ण विधेयक आए उसका प्रवर समिति या। सयुक्त समिति मे भेजना अनिवार्य बना दिया जाय ?

दूसरी बात—ये इतने हठधर्मी हैं कि विरोधियो के द्वारा सशोधन दिए जाते हैं तो खुले मन से उन सशोधनो पर विचार करने के लिए ये कभी तैयार नही हैं । क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे मे यही हुआ । कोकिंग कोल माइन्स एक्ट के बारे मे यही हुआ । तो विधेयक के बारे मे हमेशा यही होता है । अब

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विधेयक आया तब उसके बारे में भी हमने पचासों अमेंडमेंट्स दिए थे। आज सारे फाइनेंस बैंकों में हो रहे हैं। बैंकों से जो कर्जा दिया जाता है ठीक ढंग से उसका वितरण नहीं हो रहा है। यह क्यों हो रहा है, उदाहरण के लिए यह मैं कह रहा हूं। एक तो मैं यह कहूंगा कि सब महत्वपूर्ण विधेयक सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास जाने चाहिए।

दूसरी बात—मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं—प्रतिपक्ष के द्वारा जो भी संशोधन दिये जायेंगे, क्या खुले मन से एक-एक संशोधन पर विचार करेंगे और प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल न बना कर उनको स्वीकार करेंगे।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं—सरकार जब भी कोई राष्ट्रीयकरण का विधेयक ले कर आये, उसके पहले यह जरूरी होना चाहिये कि पूरी इण्डस्ट्री की समस्या का वह अध्ययन करे और राष्ट्रीयकरण को प्रचार का साधन न बनाये। सभी समस्याओं का अध्ययन करने के बाद जो विधेयक आयेगा उससे मजदूरों का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और उपभोक्ताओं का कल्याण होगा।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं—जब इन्होंने कोकिंग माइन्ज और कोल माइन्ज का राष्ट्रीयकण किया, उस समय वितरण की समस्याओं के बारे में इन्होंने सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया। स्वयं मंत्री महोदय ने अपनी भूल स्वीकार की कि स्माल इण्डस्ट्रीज का जो कोटा था, इन्होंने सोचा कि उसको कम करने से बड़ी बचत हो जायगी, लेकिन कोई बचत नहीं हुई, बल्कि स्माल इण्डस्ट्रीज बन्द होने लगी, हजारों मजदूर बेकार हुए। इनके सामने मैंने मुरादाबाद और फीरोजाबाद के उदाहरण दिये थे। अब कुछ किया है, लेकिन अभी भी शिकायतें आ रही हैं। इसलिये वितरण के बारे में सोचें, वर्ना दूसरा विधेयक लेकर इन को जल्द आना पड़ेगा। इसलिये इसके बारे में भी मैं इनकी राय जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है, उसके बारे में क्या आप कुछ कहेंगे? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आदेश दीजिये ताकि रघुरमैया साहब उसको सुनें और हमेशा किसी भी अच्छे विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेजने की हमारी दरख्वास्त को मानें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would accept as a general principle that more haste is more waste, and I think the Bill that we are discussing right now itself is an example of this. Yesterday, we adopted the motion for consideration in five minutes but now, in the general discussion on a clause, we are spending so much time that it comes to something like an hour or even more than that. I think it is very important and I would agree with Mr. Madhu Limaye that we have a very great responsibility and this Bill which touches hundreds of thousands of our people has got to be gone into very very carefully. If we do a clause in a hurry, we will not only get ourselves into trouble but, perhaps, it will create confusion in the country. It would be a good thing that we go through every Bill carefully not only on the part of the Government which prepare the Bill but we have also a responsibility in this House. I think we are very fortunate in this House that we do have some very hardworking, very able and very painstaking members who go through every little detail. We should be grateful for that. It is very good for the democracy.

SHRI MADHU LIMAYE: Thank you, Sir.

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI T. A. PAI): I am grateful to the Members for giving support to this amendment. The only complaint has been that when these

[Shri T. A. Pai]

amendments were suggested to the original Bill, the Government had not accepted them, that it should have been more graceful if they had not done so and that now the Governmtnt comes too late in the day to accept this

Anyway, the hon Members would remember that when the non-coking coal mines were nationalised, these provisions were incorporated and if at this stage, the Government has come to make amendments in order that the workers' interests may be protected, particularly, in view of the fact that when we look into the accounts deeply, we find considerable arrears of amount under provident fund and arrears under statutory liabilities to the employees due and since we had appointed a Commissioner of Payments and we are entrusting him the due amount, we thought it was neecssary for us to come before this House and get this amended so that justice that was due to the workers could be done

I entirely agree that it would be most desirable to go into all the aspects beforehand because particularly in this case when you look at the figure of the PF alone due to the employees it comes to Rs. 6 crores in the coking coal mines and in the other coal mines it comes to about Rs. 10 crores. I don't know what exactly the liabilities under gratuity and other things would be but at least in the case of royalty still it would be not less than Rs 10 crores under this and another Rs 20 crores under the other Act. I do not know what will be left to be recovered by the other creditors, secured and unsecured. Some hon. Members suggested to me: Attack the culprits, send them to jail, take this action, take that action, and so on. I wish all this was thought of very much earlier because the mineowners are not just individuals; in some cases they are all limited companies and once their assets are getting extinguished, what will happens, there is practically no liabilities, because the liabilities are limited except to the extent that they have given personal guarantee and in case the security gets exhausted the workers have a right to proceed against them

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Many companies have other assets and business.

SHRI T. A. PAI. When you legislate you legislate for all. There might be surplus in some cases; there might be heavy deficit in some other cases. I am unable to give you a case by case analysis of that the situation would be On the whole while we have decided to give compensation of Rs 16 crores under this Act and another Rs. 40 lakhs which comes by way of interest and Rs 56 lakhs by way of mnagement expenses and so on, these are all personal liabilities that have got to be met The liabilities due to employees as PF amounts, as statutory liabilities, etc would be deducted and they will have a priority before any secured or unsecured liabilities of the company Questions were asked about the awares Suppose it is a statutory award and under it commitments have not been kept up If it was voluntary advice which was not carried out I am unable to say anything If there are agreements which are equally enforceable and the commitments have not been kept up If there are any bonuses declared which is payable and in regard to which they fail, all these will comes under the wages and they will be deducted before any other payments are made

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: What about proceedings pending before Industrial Tribunals at that time of nationalisation? What will happen to those proceedings?

SHRI T A. PAI: Whatever liability there are against those owners, if they fall under this category, they will be accepted In other categories they have got other civil remedies and every little thing cannot be protected by any legislation that we could think of We have conferred some more privileges by the enforcement of this enactment.

So far as the amendments moved by my hon. friends are concerned, I appeal to them to reconsider those amendments. I am unable to accept them Mr. Ramavatar Shastri has pleaded for employees' participation in the management. I entirely agree because that is the policy of

the Government and we see that employees' participation must be ensured gradually.

What are the modalities of all these? We have got a wage negotiating committee which will be sitting at all times between the employees and the coal authorities and I do hope that they will be arriving at some kind of participation arrangements. Whenever the word 'participation' is mentioned', it means something to the employer and entirely something different to the employee. I would very much like that these modalities are worked out so that the employees may have the sense of participation at all stages. So far, it has not been suggested. Let them be elected so that the claims of individual miners could be placed before them. We felt that individual members could not ask for this; nobody pressed forward their claims. This responsibility shall be taken over by the Commissioner for Payments.

Another suggestion was made to me in the other House which I have accepted. By executive orders. I have said that even the labour unions will be permitted to make representation on behalf of the employees regarding the claims. I hope that there should be no difficulty at all for any employee to prove his liabilities and get his money collected. But, I have not provided for in the Bill. By executive orders, we shall provide that they will have the right. The fundamental right is that of the employee himself to claim the amount that is due to him. What we are trying to do is this. The amount that is due to them should be given so that they may not suffer in collecting the money that is due to them.

SHRI K. D. MALAVIYA (Domariaganj) How do you realise that?

SHRI T. A. PAI: It is all a question of bringing up the facts of the case because, what is due to them or what is not due to them has to be decided by the Commissioner for Payments.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Under the Payment of Wages Act, any labour union can go to the court and claim the wage of the worker. Why should not that sort of provision be included in the Act itself?

SHRI T. A. PAI: There are many unions. We could not think it possible to include it. We are only trying to see that this right is conferred on them.

SHRI K. D. MALAVIYA: I would like to know from him whether the claims of the workers—employees—come under the Compensation Fund?

SHRI T. A. PAI: Out of the Compensation Fund, all the amounts due to the labour will have precedence.

The difficulties of the Gorakhpuri labourers organisation have been placed before me. Many hon. Members have also pointed out to me that my predecessor had made a certain commitment to the House that their problem would be looked into. I shall certainly keep up those commitments because I know that it is one problem. So far as the existing labour is concerned, we have tried to see that they all have been absorbed. They have served that organisation for a long time. I should see what can be done to them.

Another problem that has been pointed out to me is with regard to seven employees of the Coal Mines Association. I do not know what exactly the function of the Association is. But, in the course of taking over of coking coal mines, we have almost absorbed about 30,000 more employees then were registered with the Provident Fund Commissioner. According to us we have some surplus labour. It does not matter. With the development of the mines that we are now going ahead, we should be able to make use of them. I shall see how exactly these seven surplus people could be made use of. I may assure the hon. Members that when we take over the industry depending upon their own merits, if they are found suitable for employment, they will get precedence over the others. I cannot give any commitment that they would all be absorbed.

SHRI B. R. KRISHNAN: What have you done with regard to pending cases?

SHRI T. A. PAI: Another point that has been raised is this. Why, immediately after nationalisation, has the production of coal fallen? I say that after nationalisation the pattern of production had undergone a change. The requirements of the thermal plants have been going up year by year. The production and consumption of coal by the thermal plants have also been mounting As a matter of fact, in the Fourth Five Year Plan, the requirements of coal to meet the needs of the thermal plants were of the order of 19 million tonnes. If the installed capacity of the plant for the Fifth Five Year Plan goes through, this will be stepped up to 50 million tonnes of coal for power supply alone.

If the steel industry target of 14 million tonnes is to be assured, then I am afraid that the coking coal production will have to be stepped up to 28 million tonnes instead of the 18 million tonnes that was planned to be produced this year.

Apart from that, it is a fact that between 1968 and now, the production of soft coke which supplies the fuel requirements of UP, Bihar, Bengal and the cities of Delhi and Kanpur to a very large extent, where the common people are involved, went down from 3.5 million tonnes to 2.5 million tonnes, because this was not considered very important. When the priorities for the steel plants, for the industries, for small-scale industries, and for power generation all went up, the railways were compelled to give the lowest priority to this. But anyway, we have revised this lately, and we have set up a committee at the point near the coal mines, which consists of the railway authorities, the Coal Authority and the Steel Authority coordinating at that level, and here at this level, the Railway Ministry and my Ministry have been coordinating completely to see that at least the movement is stepped up by 1000 wagons extra per day until sufficient stocks of all these types of coal are built up.

I assure the House that the production of soft coke will be stepped up from 2.5 million tonnes to 4 million tonnes with which I feel that the requirements of the country should be sufficiently met. But I have still problems.

Even the going up of this production by itself is going to be a herculean task. Increasing the production of coal from 70 million tonnes to 140 million tonnes in five years is not going to be a small effort; it is going to be a very big effort. But what about the transportation? If we are going to depend entirely on the railways, then transportation would not be possible. Therefore, we are trying to have a total transport approach to this problem, and we have approached the Planning Commission as well as the Ministry of Transport to see that as far as possible, coastal shipping and inland waterways within the country are also fully utilised for moving coal over long distances. We have established a linkage, through a linkage committee, between particular generation plants and the coalfields, so that the supply of coal to the power plants is not held up.

I assure the House that while I am aware of the dissatisfaction that is there, I am aware of the prices having gone up in some places, I am aware of the shortages here and there and so on, by the time we meet next, I shall be able to report a much more satisfactory progress in the movement as well as in the bringing down of prices.

My hon. friend has pointed out to me the difficulties of the small scale industries, particularly the bangle-makers of Firozabad. Actually, we had tried to move six rakes, and six rakes have been moved, but now I understand that they have gone only to a few persons there, and a few persons have been able to corner all the stocks In any case, I shall have to look into the matter again and see that the State Government is involved in this distribution.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा उन्हीं को था जिन्होंने लिया है । बाकी लोगों को नहीं भेजा है ।

SHRI T. A. PAI: Anyway, it was found that they were asked to designature some persons, and rightly or wrongly, some

persons might have been designated, and coal has moved, but perhaps it has not reached everyone; some people might have taken advantage of it. I shall certainly look into it and see that there is more equitable distribution of coal

SHRI SOMNATH CHATTERJEE May I know whether the Coal Mines Authority will implement all the recommendations of the Central Wage Board in future, so far as the nationalised collieries are concerned?

MR DEPUTY-SPEAKER I am not allowing any more questions now Now, I shall put the amendments to vote

SHRI RAMAVATAR SHASTRI I would like amendment No 1 to be put to vote separately.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE I would like amendment No 2 to be put to vote separately

(डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय मंदसौर)

अध्यक्ष जी [illegible]।

MR DEPUTY SPEAKER Only those amendments which you want to press will be taken separately and put to vote The others which you do not want to press will be disposed of by voice vote

I shall now put amendment No 1 to the House.

*Amendment No 1 was put and negatived*

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is

Page 3,—
*after* line 3,—*insert*—

"(4A) In case the amount paid to the Commissioner under section 21 is less than the total amount of arrears referred to in sub-section (1), then the Central Government shall pay, within one month from the date of determination under sub-section (4), the amount of difference to the Commissioner and shall be entitled to recover the same from the owner of the coking coal mine or group of coking coal mines or coke oven plant, as the case may be, as if it were an arrear of land revenue" '

*The Lok Sabha divided*

Division No. 21] [15.47 hrs.

**AYES**

Bade, Shri R V

Bhattacharyya, Shri Dinen

Bhattacharyya, Shri S P

Chatterjee Shri Somnath

Dandavate, Prof Madhu

Dutta, Shri Biren

Goswami, Shrimati Bibha Ghosh

Haldar, Shri Madhuryya

Halder, Shri Krishna Chandra

†Hashim, Shri M. M

Hazra, Shri Manoranjan

Joarder, Shri Dinesh

Joshi, Shri Jagannathrao

Kachwai, Shri Hukam Chand

Krishnan, Shri E R.

Krishnan Shri M. K

Limaye, Shri Madhu

Mavalankar, Shri P. G

Mayavan, Shri V.

Mehta, Shri P M.

Mukherjee, Shri Samar

Mukherjee, Shri Saroj

---

†Wrongly votes for Ayes.

Nayar, Shri Baksi
Nayar, Shrimati Shakuntala
Pandeya, Dr. Laxminarain
Patel, Shri H. M.
Pradhan, Shri Dhan Shah
Roy, Dr. Saradish
Saha, Shri Ajit Kumar
Sezhiyan, Shri
*Shastri, Shri Ramavatar
†Shukla, Shri B. R.
Singh, Shri D. N.
Subravelu, Shri
Viswanathan, Shri G.
Yadav, Shri G. P.

NOES

Aga, Shri Syed Ahmed
Agrawal, Shri Shrikrishna
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Ambesh, Shri
Appalanaidu, Shri
Awdhesh Chandra Singh, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shri
Banerji, Shrimati Mukul
Besra, Shri S. C.
Bhargava, Shri Basheshwar Nath
Bhatia, Shri Raghunandan Lal
Chandrashekharappa Veerabasappa, Shri T. V.
Chaturvedi, Shri Rohan Lal
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chhutten Lal, Shri
Chikkalingaiah, Shri K.
Choudhury, Shri Moinul Haque
Daga, Shri M. C.
Das, Shri Anadi Charan
Das, Shri Dharnidhar
Deo, Shri S. N. Singh
Desai, Shri D. D.
Deshmukh, Shri K. G.
Dhamankar, Shri
Dharia, Shri Mohan
Dumada, Shri L. K.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Engti, Shri Biren
Gautam, Shri C. D.
Gogoi, Shri Tarun
Gowda, Shri Pampan
Hansda, Shri Subodh
Jamilurrahman, Shri Md.
Jeyalakshmi, Shrimati V.
Jha, Shri Chiranjib
Kadam, Shri J. G.
Kadannappalli, Shri Ramachandran
Kailas, Dr.
Kapur, Shri Sat Pal
Kasture, Shri A. S.
Kotoki, Shri Liladhar
Kushok Bakula, Shri
Lakshminarayanan, Shri M. R.
Mahajan, Shri Y. S.
Malaviya, Shri K. D.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mirdha, Shri Nathu Ram
Mishra, Shri Jagannath
Modi, Shri Shrikishan
Mohammad Tahir, Shri
Mohapatra, Shri Shyam Sunder
Nahata, Shri Amrit
Negi, Shri Pratap Singh
Palodkar, Shri Manikaro
Pandey, Shri Damodar

*He voted by mistake from a wrong seat and later informed the Speaker accordingly.

†Wrongly votes for Ayes.

Pandey, Shri Krishna Chandra
Pandey, Shri Narsingh Narain
Pandey, Shri R. S.
Pandey, Shri Sudhakar
Panigrahi, Shri Chintamani
Paokai Haokip, Shri
Parashar, Prof. Narain Chand
Patil, Shri C. A.
Patil, Shri E. V. Vikhe
Patil, Shri S. B.
Raghu Ramaiah, Shri K.
Rajdeo Singh, Shri
Ram Dhan, Shri
Ram Sewak, Ch.
Ram Swarup, Shri
Rao, Shrimati B. Radhabai A.
Rao, Shri Jagannath
Reddi, Shri P. Antony
Reddy, Shri P. Narasimha
Richhariya, Dr. Govind Das
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Rudra Pratap Singh, Shri
Saini, Shri Mulki Raj
Samanta, Shri S. C.
Sanghi, Shri N. K.
Sathe, Shri Vasant
Sayeed, Shri P. M.
Sethi, Shri Arjun
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri Nawal Kishore
Sharma, Shri R. N.
Shastri, Shri Biswanarayan
Sher Singh, Prof.
Shivnath Singh, Shri
Singh, Shri Vishwanath Pratap
Sinha, Shri R. K.
Sokhi, Shri Swaran Singh
Stephen, Shri C. M.
Suryanarayana, Shri K.
Tiwari, Shri Chandra Bhal Mani
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Unnikrishnan, Shri K. P.
Verma, Shri Ramsingh Bhai
Verma, Shri Sukhdeo Prasad
Vidyalankar, Shri Amarnath
Yadav, Shri R. P.

MR. DEPUTY-SPEAKER. The result* of the division is:

Ayes: 36; Noes: 104.

*The motion was negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put amendments Nos. 3 and 4 to vote.

*Amendments Nos. 3 and 4 were put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is.

"That clause 4 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

*The following members also recorded their votes for Noes:—
Sarvashri Madho Ram Sharma, Jagdish Narain Mandal, Mani Ram Godara, P. R. Shenoy, Genda Singh, M. M. Hashim and B. R. Shukla.

[Mr. Deputy-Speaker]

**Clause 5—(Amendment of section 23)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Pandeya, are you moving your amendment?

DR. LAXMINARAIN PANDEYA: Yes, Sir. I move:

'Page 3, line 34, *add* at the end

"and before filing the claims the Commissioner shall consult workers' representative from the concerned mine elected specifically for this purpose."' (5)

**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : उपाध्यक्ष जी, मेरा संशोधन भी इसलिये दिया गया है कि भविष्य निधि आयुक्त के साथ कर्मचारियों के और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय और ऐसे प्रतिनिधि मिल कर कर्मचारियों और श्रमिकों के दावे के सम्बन्ध में दावे प्रस्तुत करवा सकें । आपको मालूम है कि करोड़ों रु० की राशि श्रमिकों की भविष्य निधि के रूप में बाकी है और जो दावे उनके हुए हैं वे बहुत कम हैं । हजारों की संख्या में दावे लगाये जा सकते हैं । उन सब को एकत्र करना और किसी कर्मचारी का कोई दावा बाकी न रहे इस प्रकार की कार्यवाही के लिये यदि आयुक्त के साथ कर्मचरियों और श्रमिकों के निर्वाचित प्रतिनिधि रखे जायें तो मैं समझता हूं कि उसका लाभ श्रमिकों को मिल सकेगा । इसलिये जहां इस प्रकार का प्राविधान किया गया है धारा 5 के अन्दर कि :

"....किसी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान या किसी अन्य निधि के बारे में दावे इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों की ओर से कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस कीम अधिनियम, 1948 की धारा 3ग के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त द्वारा फाइल किये जा सकते हैं ...." और इसी के अन्त में यह कि दावे भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इनके साथ में मैं चाहता हूं कि निम्न पंक्तियां जोड़ दी जायें :

"और दावे फाइल करने से पहले आयुक्त सम्बन्धित खान के कर्मकारों के प्रतिनिधि से, जिसे इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट निर्वाचित किया जायेगा, परामर्श करेगा ।"

इससे समय भी बचेगा और आज जो कर्मचारियों को कठिनाइयां पैदा हो रही हैं उनके बारे में सहूलियत पैदा होगी । मैं समझता हूं मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे । कर्मचारियों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिये ।

SHRI T. A. PAI: I beg to move:

be accused that I am always unreasonable in accepting a reasonable proposition, but I do not consider that this amendment is necessary. I am unable to accept it for the simple reason that for the sake of getting this an election is to be held and an employee is to be elected. Ultimately, while there are so many unions, I do not want one more conflict among them. What is most important is to prove urgently the claims of the individual employee who will be assisted by the Commissiner for Provident Fund, and he can be assisted by his own union in arriving at a figure. With this I think the Member must feel satisfied that there will be enough protection given to the employee concerned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall put the amendment to the vote.

*Amendment No. 5 was put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

*"That clause 5 stand part of the Bill"*

*The motion was adopted.*

*Clause 5 was added to the Bill.*

Clause 6, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI T. A. PAI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह जो बिल है इसका हम स्वागत करते हैं। इस बिल में यह कहा गया है कि प्राविडेंट फंड तथा अन्य प्रकार का जो पैसा मालिकों से लेना है उसको लेने के लिए प्राविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा मुकदमे चलाये जायेंगे और उनसे पैसा वसूल किया जायेगा। चार लाख कर्मचारी जो कोयला खानों में काम करते हैं उन की रकम लगभग 70–80 करोड़ मालिकों की तरफ निकलती है। इस में ग्रेचुइटी, बोनस, वेतन तथा अन्य प्रकार के वलफेयर की राशियां सब शामिल हैं। लेकिन आप अधिकार दे रहे हैं केवल प्राविडेंट फंड के बारे में। बाकी जो उनके ड्यूज़ हैं उनके लिए कौन मुकदमे लड़ेगा ? यूनियन मुकदमे लड़ सकती है इसके लिए भी आपने अधिकार नहीं दिये। कमिश्नर के साथ जुड़ कर वह काम कर सकती है इसको भी नहीं माना। मैं चाहता हूं कि जितनी भी रजिस्टर्ड हैं युनियनज है उन को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे मजदूरों के झगड़े स्वयं जा कर लड़ सकें या कमिश्नर के साथ—जुड़ कर मुकदमे लड़ सकें और मुकदमे पर निगाह रख सकें।

यह कहा गया है कि कम्पेंशेशन में से पैसा रोका जायेगा। लेकिन इस पैसे से पूरा पड़ने वाला नहीं है। खानों को आपने अपने हाथ में लिया। आपने किसी को पचास परसेंट, किसी को सौ सेंट परसेंट, किसी को 105 परसेंट, किसी को 25 परसेंट मुआवजा दिया। उस में काफी रकम चली गई है। अब आप क्या करेंगे ? अगर और पैसे की जरूरत हुई तब उस को उन से कैसे वसूल करेंगे। यह कहा गया है कि उन की सम्पत्ति लेकर, उस को बेच कर पैसा मजदूरों का जो देना है वह दिया जाए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। कोयले की खानों को आपने अपने हाथ में लिया। उन में जो मुनाफा होता है सरकार को उस में से पैसा मजदूरों को दिया जाए, मजदूरों का जो वेतन आदि का बकाया है वह दिया जाए। या फिर सरकार अलग से पैसा इस के वास्ते दे।

गोरखपुरी मजदूरों की बात कही गई है। उन की दशा बहुत ही खराब है, दयनीय है। जैसे कैदियों को जेलों में रखा जाता है, उसी तरह से उनको भी रखा जाता है कैदियों जैसा व्यवहार उन के साथ होता है। ये कम्पाउंड के बाहर घूमने के लिये नहीं जा सकते हैं। उन का खाना सामूहिक बनता है। वह बहुत ही खराब होता है। नपा तुला हुआ खाना उन को मिलता है। मैंने उसको स्वयं खा कर देखा है। आप को याद होगा कि मैं ने सदन में लाकर भी उसको दिखाया था। उन के भोजन की ओर ध्यान दिया जाए, उन की दशा को सुधारा जाए।

आप के कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया है। इसे पहले 40 किलो कोयला कोयला 6 रुपये में मिलता था और उसके बाद यह बढ़ कर बारह रुपये हो गया। यह सवाल जब सदन में उठाया गया तब श्री मोहनकुमारमंगलम ने कहा था कि दाम बढ़ने की और भी सम्भावना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों कोयला ऊंचे दामों पर मिल रहा है और पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं मिल रहा है। 40 किलों के दाम 15 रुपये हैं लेकिन फिर भी उपलब्ध नहीं है। क्या यह राष्ट्रीकरण की देन है उसकी पुण्याई है ? जिस किसी चीज़ पर हाथ डालते हैं वह मार्केट से गायब हो जाती है। वह उपभोक्ताओं को उचित

**श्री हुकम चन्द कछवाय**

दाम पर और पर्याप्त मात्रा मे मिलनी चाहिये। छोटे उद्योगो को उचित दामो पर मिलनी चाहिये। लेकिन ऐसा नही हो रहा है। उस के कारण आज काफी उद्योग बन्द होते जा रहे हैं और उन मे लगे हुए मजदूर बेरोजगार होते जा रहे है। फीरोजाबाद में चूडी बनाने के कारखाने बन्द हो रहे हैं। अनेको उद्योगो के उत्पादन मे कमी आ रही है। बाजार के अन्दर दाम बढ़ रहे है :

मै चाहता हू कि आप जो कहे वह करे। लेकिन आप कहते कुछ है और करते कुछ और ही है। हाथी के दान्त खाने के और और दिखाने के और। यही हालत आपकी है। यह नही होना चाहिये। आप जो बिल लाये है इसकी भावना अच्छी है लेकिन इसका लाभ तभी होगा जब ईमानदारी मे इस पर अमल किया जाये। हर बीमारी की दवा राष्ट्रीयकरण ही आप मानते है लेकिन यह सही नही है। आपको किसी भी समस्या के हर पहलू पर विचार करना चाहिये। सम्बद्ध लोगो से सलाह लेनी चाहिये। आप जो अफसर कोयला खानो मे भेजते है वे टेक्नीकल नही है। आई० ए० एस० अफसर भेज दिये गये है अथवा दफ्तरो मे उच्च अधिकारी भेज दिये गए है जिन को कोयला खानो के बारे मे कोई अनुभव नही है, जिनको इस काम का तजुर्बा नही है। जो उस क्षेत्र के विशेष लोग है अथवा जिन्हे खान सम्बन्धी जानकारी है, उन को ही भेजा जाना चाहिये ताकि लोगो को राहत मिल सके और काम अच्छी तरह से चल सके।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Sir, I fully support the amendments that have been brought here. The question is whether after nationalisation any objective planning has been done in regard to the coalmines. In 1963 the Estimates Committee in their report on NCDC recommended that broad principles regarding the financial and economic obligations of public undertakings should be laid down by Government. So far this has not been done. Though the coal mines have been nationalised, the spirit of the old mine-owners who looted the country still remains There is chaos everywhere and production has gone down. In the distribution machinery also, there is chaos. Even in Delhi you do not get coal for your kitchen Your servant will stand in the qneue and may get 5 kilos of coal. In Calcutta and other areas also the position is the same and the prices are going up

You have to remove bureaucratism totally from the nationalised mines The minister said that wage Board recommendations will be implemented. But on 30th June 1973 the Coal Mining Authority refused to give annual increment, which is a clear recommendation of the wage board in the Basswa colliery in Dhanbad, there is a serious dispute.

MR DEPUTY-SPEAKER. In the third reading, the scope is limited to advancing arguments either in support of the Bill or against it

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: I am supporting the Bill

MR DEPUTY-SPEAKER Are all these things relevant for that purpose?

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: They have brought this Bill and nationalised the coal mines

MR DEPUTY-SPEAKER: This is not the Bill to nationalise the coal mines.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: It is provided in the Bill that from the compensation, workers' dues will be paid. In connection with that, I am making my submissions They have not yet been able to fully scrutinise the registers of the miners in every mine, so that the actual miners who were working before the take-over may get their employment in the mines and also their dues. It was assured by the ministry that this will be

done within a short time, but that has not been done yet. So, the minister should look into the matter and see that these bureaucrats do not spoil the atmosphere by refusing their due increments and other benefits, creating chaos thereby. That should be looked into so that the workers may also get enthused to produce more after the nationalisation of the coal industry.

**16.00 hrs.**

SHRI P. M. MEHTA: Sir, nationalisation is not an end in itself it is only a means, an instrument, for the social good. I hope the Government would not use this instrument only for political popularity and with an eye on the elections. After nationalisation we find, especially in my part of the country, that there is an acute shortage of coal. In my own home town workers in many industries are laid off for shortage of coal. The price of coal is also going up because of shortage of coal. The first thing that requires the attention of the Ministry is adequate supply of coal.

It is a matter of regret that immediately after nationalisation 5,000 workers of Bihar coalmines were retrenched for no fault of theirs. Either they must be taken in the very same mines or they must be provided alternative employment.

Then you would be surprised to know that a social security scheme like pension has been stopped in some of the mines after the nationalisation of coalmines. In spite of the repeated demands of the workers for the continuance of the pension scheme, the management has turned a deaf ear to their requests for pension even after putting in a service of 30 or 35 years. This must be rectified by the management. It is a matter of shame for the Government that after nationalisation they have stopped a benefit which the workers were enjoying prior to nationalisation.

The hon. Minister has said that there is a proposal under consideration for transport of coal by sea. If coal is transported by sea to the port towns, it will solve the problem of shortage of coal to some extent. But since the transport cost by sea is higher than that by land, the industry will not be able to afford it unless some subsidy is given for transport of coal by sea. I hope the Minister will consider this point.

SHRI T. A. PAI: Sir, I have already answered most of the points that were raised in the subsequent debate. I know in Gujarat there has been shortage. As pointed out by hon. Members, most of our problems of transport would be solved only by having a total approach to the transport problem. I know that railway transport is cheaper because it is subsidised. We shall try to see that a system of transport rates is worked out which is fair to all. I have already pointed out that the needs of the power plants, the steel plants and the industries, both large and small, will be given priorities. So far in the matter of brick-burning coal and the soft coke required by the majority of the people the consumer has not been given enough importance. Recently in a conference with the railways we have come to the conclusion that this must be given some priority.

I never said that the coal prices are fair. I never commented on the prices. I only pointed out that I am aware that the prices are high in the market and it will be our endeavour to see that we take steps as soon as we can to have dumps built up, and sufficient stocks, so that we might be able to maintain prices and see that consumers are able to get it at reasonable prices.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

---

**16.06 hrs.**

## MOTION RE: APPROACH TO THE FIFTH PLAN—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up further consideration of the motion to consider the 'Approach to the Fifth Plan'.